राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रकाशित एवं ई गवर्नेंस बुलेटिन

इंफोर्मेटिक्स

वॉल्यूम 31, सं 3, जनवरी, 2023

संपादकीय संयोजन : प्रिस्का लाकड़ा

माननीय प्रधानमंत्री ने 75 डिजिटल बैंक इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) को राष्ट्र को समर्पित किया। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाएगी और नागरिकों के लिए बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाएंगी। उन्होंने कहा कि डीबीयू आम नागरिकों के लिए सुगम जीवन (ईज ऑफ लिविंग) की दिशा में एक बड़ा कदम है और बताया कि इस तरह के बैंकिंग सेटअप में सरकार का लक्ष्य न्यूनतम बुनियादी ढांचे के साथ अधिकतम सेवाएं प्रदान करना है और यह सब बिना किसी कागजी कार्यवाही के डिजिटल रूप से होगा। यह एक मजबूत और सुरक्षित बैंकिंग प्रणाली प्रदान करने के साथ-साथ बैंकिंग प्रक्रिया को भी सरल करेगा।

वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण के दौरान, वित्त मंत्री ने हमारे देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 जिलों में 75 डीबीयू स्थापित करने की घोषणा की। डीबीयू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्थापित एक विशेष फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस हब है, जो डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के साथ-साथ किसी भी समय स्वयं-सेवा मोड में डिजिटल रूप से मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की सेवा के लिए कुछ न्यूनतम डिजिटल बुनियादी ढाँचे का निर्माण करता है। डीबीयू की स्थापना देश के कोने-कोने में डिजिटल बैंकिंग के लाभ को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा।

डीबीयू उन लोगों को सक्षम करेगा जिनके पास सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का बुनियादी ढांचा नहीं है, वे बैंकिंग सेवाओं तक डिजिटल रूप से पहुंच सकेंगे और उन लोगों की भी सहायता करेंगे जो डिजिटल बैंकिंग को अपनाने के लिए तकनीकी जानकार नहीं हैं। डीबीयू के माध्यम से दी जा रही सेवाओं में बचत खाता खोलना, बैलेंस-चेक, प्रिंट पासबुक, फंड ट्रांसफर, सावधि जमा में निवेश, ऋण आवेदन, जारी किए गए चेक के लिए भुगतान रोकने के निर्देश, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के लिए आवेदन, खाते का विवरण

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी एनआईसी वीडियोकांफ्रेंसिंग सेवा के माध्यम से देश भर में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का शुभारंभ करते हुए

देखना, करों का भुगतान, बिलों का भुगतान, नामांकन करना आदि जैसी बैंकिंग सुविधाएं शामिल हैं। डीबीयू जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से सरकारी क्रेडिट लिंक योजनाओं के लिए ऑनबोर्डिंग की सुविधा प्रदान करेंगे और छोटे टिकट एमएसएमई/ खुदरा ऋणों की एंड-टू-एंड डिजिटल प्रोसेसिंग करेंगे।

– सूचना विज्ञान समाचार डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने आशा संगिनी पोर्टल का उद्घाटन किया

उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी दून मेडिकल कॉलेज (जीएमडीसी), देहरादून में आयोजित एक समारोह में आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) संगिनी पोर्टल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कठोर जलवायु परिस्थितियों वाला राज्य है और आशा संगिनी राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आशा संगिनी पोर्टल राज्य की सभी 12,018 आशा संगिनियों की सहायता और सशक्तिकरण करेगा। उन्होंने कहा कि आशा संगिनी का भुगतान समय पर हो, इसके लिए पोर्टल शुरू किया गया है और इससे विभाग को उनके काम का मूल्यांकन और निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल आशा संगिनियों को सेवाओं के प्रभावी और स्पष्ट हस्तांतरण में मदद करेगा।

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि 6000 आशा संगिनियों को टैब प्रदान किए गए हैं और शेष संगिनियों को जल्द ही टैब सौंपे जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक खंड में आशा संवाद कार्यक्रम आयोजित किये उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में दस लक्ष्य निर्धारित किये हैं, जिन्हें वर्ष 2025 से पहले पूरा कर लिया जायेगा।

– ए.के. दधीचि, उत्तराखंड

उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में आशा संगिनी पोर्टल का शुभारंभ किया

माननीय मुख्यमंत्री असम द्वारा मिशन बसुंधरा 2.0 का अनावरण किया गया

असम के माननीय मुख्यमंत्री, श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र सभागार में आयोजित एक आधिकारिक समारोह में राज्य के मूल निवासियों के भूमि मुद्दों के समाधान के लिए मिशन बसुंधरा 2.0 की घोषणा की।

माननीय मुख्यमंत्री ने स्वदेशी की परिभाषा को विस्तार से बताते हुए कहा कि सरकार वन अधिकार अधिनियम में दी गई परिभाषा का पालन करेगी। मिशन बसुंधरा 2.0 के तहत भूमि दावों का निपटारा स्व-प्रमाणीकरण के आधार पर किया जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि दावेदार पिछली तीन पीढ़ियों से भूमि पर रह रहा है। जब भी कोई संदेह होगा, जिला प्रशासन दावेदार के खिलाफ जांच करेगा।

मिशन बसुंधरा 2.0 के तहत सरकारी खास और सीलिंग अधिशेष भूमि का बंदोबस्त हैं; अधिभोगी किरायेदारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना; हस्तांतरित वार्षिक पट्टा भूमि का बंदोबस्त; वीजीआर/पीजीआर भूमि का बंदोबस्त; स्वदेशी विशेष कृषकों (चाय, कॉफी, रबर आदि) के लिए भूमि का बंदोबस्त; आदिवासी समुदायों, दूसरों के बीच की वंशानुगत भूमि का बंदोबस्त संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

– कविता बरकाकोटी, असम

असम के माननीय मुख्यमंत्री, डॉ हिमंत बिस्वा सरमा, गुवाहाटी में मिशन बसुंधरा 2.0 का शुभारंभ करते हुए

माननीय मुख्यमंत्री पंजाब ने खंगी तकसीम पोर्टल लॉन्च किया

माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजस्व विभाग के कामकाज को डिजिटल बनाकर नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के प्रयास में 'खंगी तकसीम' नामांकन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक ऑनलाइन सेवा समर्पित की। सेवा का शुभारंभ करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक अब एक क्लिक के साथ अपना खंगी तकसीम' आवेदन जमा कर सकते हैं। यह भूमि सीमांकन प्रक्रिया की मात्रा निर्धारित करेगा और भूमि खरीदने और बेचने में आसानी सुनिश्चित करेगा। इससे फसल क्षति का मुआवजा प्राप्त करने और जमाबंदी की प्रति प्राप्त करने में भी सुविधा होगी।

आवेदकों को केवल अपने मूल विवरण जैसे नाम, पिता/ पति का नाम, गांव का नाम, उप-तहसील/ तहसील, जिला, खाता और खेवट संख्या जैसे बुनियादी विवरण के साथ प्रस्तावित विभाजन के एक ज्ञापन और विधिवत हस्ताक्षरित भूमि के हिस्से वाले पार्सल को दर्शाते हुए फील्ड मैप सभी शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है । संबंधित अंचल राजस्व अधिकारी द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद आवेदन कानूनगो प्रभारी और फिर संबंधित पटवारी को भेजा जाएगा। सत्यापन के बाद, पटवारी आधिकारिक औपचारिकताओं के लिए पार्टियों को बुलाएगा और म्यूटेशन की कार्यवाही शुरू करेगा। आवेदन eservices.punjab.gov.in पर देखा जा सकता है ।

– परमिंदर कौर, पंजाब

पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री, श्री भगवंत मान ने राज्य में खंगी तकसीम को कारगर बनाने के लिए समर्पित सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया

माननीय केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने जैव ऊर्जा और जैव गैस पोर्टल लॉन्च किए

श्री आर.के. सिंह, माननीय केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा आयोजन में एक कार्यक्रम के दौरान जैव ऊर्जा और जैव गैस पोर्टल का शुभारंभ किया। माननीय मंत्री ने अपने संबोधन में बायोगैस के माध्यम से स्वच्छ खाना पकाने, बायोमास पेलेट्स और ब्रिकेट्स और परिवहन के लिए बायोसीएनजी का उपयोग करके ताप विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग प्रदान करने के लिए बायोएनर्जी के महत्व को बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिशेष बायोमास के उपयोग का लाभ किसानों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में ग्रामीण परिवारों तक पहुंचना चाहिए।

बायो ऊर्जा पोर्टल को सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है ताकि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स, बायोमास ब्रिकेट / पेलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और बायोमास (नॉन-बैगास) आधारित कोजेनरेशन प्रोजेक्ट्स को केंद्रीय वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा और पंजीकृत किया जा सके। जैवगैस पोर्टल लाभार्थियों को राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत जैवगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए ऑनलाइन प्रस्तावों और अनुमोदन की सुविधा प्रदान करता है। लाभार्थी छोटे/मध्यम बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और निरीक्षण की वर्तमान स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

अपने मुख्य भाषण के दौरान, माननीय मंत्री ने न केवल इसकी ऊर्जा क्षमता बल्कि इसके साथ जुड़े बड़े सामाजिक-आर्थिक लाभों के कारण भी जैव ऊर्जा को बढ़ावा देने की आवश्यकता को दोहराया।

– सूचना विज्ञान समाचार डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

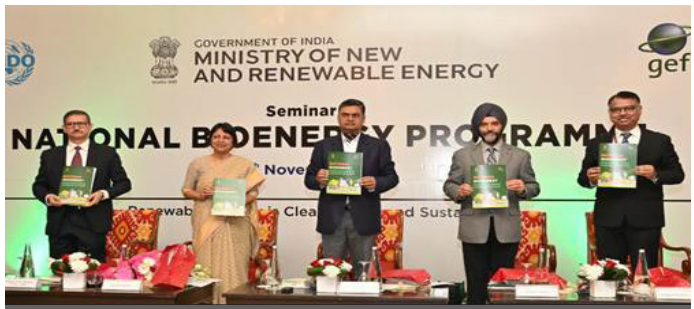

माननीय केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री आर.के. सिंह, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, नई दिल्ली में जैव ऊर्जा और जैव गैस पोर्टल का शुभारंभ करते हुए

मणिपुर सरकार ने मणिपुर राज्य व्यावसायिक कर एप्लिकेशन की शुरुआत की

मणिपुर सरकार ने राज्यव्यापी व्यावसायिक कर नामांकन अभियान के शुभारंभ पर मणिपुर राज्य व्यावसायिक कर आवेदन एप्लिकेशन शुरू किया। एप्लिकेशन को आधिकारिक तौर पर मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। यह करदाताओं को करों का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन नामांकन की सुविधा प्रदान करता है और इसे https://professionaltax.mn.gov.in पर देखा जा सकता है।

मणिपुर राज्य व्यावसायिक कर भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 से लिया गया है जो मणिपुर राज्य सरकार को व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगार पर 2500 रुपये सालाना की अधिकतम सीमा के साथ व्यावसायिक कर लगाने का अधिकार देता है।

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन कर प्रशासन और अनुपालन के साथ व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कम समय में इस एप्लिकेशन को तैयार करने के लिए एनआईसी के अधिकारियों के समन्वय और कड़ी मेहनत के लिए उनकी सराहना की।

– सूचना विज्ञान समाचार डेस्क, एनआईसी–मुख्यालय

मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री, श्री एन. बीरेन सिंह ने राज्यव्यापी कर नामांकन अभियान के दौरान मणिपुर राज्य व्यावसायिक कर एप्लिकेशन का शुभारंभ किया

मुख्य सचिव ओडिशा ने सीएमसी, ओएचपीसी, और एसजेएसयू के लिए ई–ऑफिस लॉन्च किया

ओडिशा के मुख्य सचिव श्री सुरेश चंद्र महापात्रा ने आधिकारिक तौर पर कटक नगर निगम (सीएमसी), ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन (ओएचपीसी) और श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय (एसजेएसयू) के लिए ई-ऑफिस शुरू किया।

सिस्टम लॉन्च करते हुए, मुख्य सचिव ओडिशा ने कहा कि ई-ऑफिस ने शासन को वर्तमान और भविष्य के लिए तैयार कर दिया है। इसने सरकारी कामकाज के संचालन को अधिक तेज, सटीक और उत्तरदायी बना दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कार्यालयों के बरामदे में फाइलों के बंडलों को ले जाना, महीनों तक फाइलों का लंबित रहना, फाइलें गायब होना और फाइलों के साथ शरारत करना अब अतीत की कहानियां हैं, ई-ऑफिस ने सिस्टम में बहुत जरूरी पारदर्शिता का संचार किया है ।

मुख्य सचिव ओडिशा ने ऑफिस ऑटोमेशन के लाभों की गणना की और सीएमजीआई और एनआईसी को उन सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस के आवेदन के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करने के लिए कहा जो ओडिशा सचिवालय वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम (ओएसडब्ल्यूएएस) नेटवर्क में शामिल नहीं हैं।

– हरा प्रसाद दास, ओडिशा

ओडिशा के मुख्य सचिव ने राज्य लोकसेवा भवन, भुवनेश्वर में सीएमसी, ओएचपीसी और एसजेएसयू के लिए ई–ऑफिस लॉन्च किया

सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संशोधित ई–ग्रामस्वराज पोर्टल लॉन्च किया

श्री शैलेश कुमार सिंह, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच भारत सरकार द्वारा आयोजित जन योजना अभियान 2022 नई दिल्ली पर दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान पंचायतों द्वारा विषयगत योजना के लिए संशोधित ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया ।

सचिव ने पंचायती राज मंत्रालय (MoPR), MoRD और भूमि सुधार विभाग (DoLR), भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की निगरानी के लिए एकीकृत डैशबोर्ड भी लॉन्च किया। डैशबोर्ड को NIC ने अपने तेजस-IV टूल का उपयोग करके विकसित किया है। डैशबोर्ड को https://egramswaraj.gov.in/mprDashboard.do पर देखा जा सकता है।

ईग्रामस्वराज पोर्टल ने पंचायतों में डिजिटलीकरण को मजबूत किया है। इसमें सरलीकृत कार्य-आधारित लेखांकन अनुप्रयोग है और इसे ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत पंचायत एंटरप्राइज सूइट के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। इसमें नियोजन, रिपोर्टिंग और लेखांकन के लिए विभिन्न मॉड्यूल हैं और डिजिटल भुगतान सहित दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को कैप्चर करता है।

इसका उद्देश्य पूरे देश में पंचायती राज संस्थानों में बेहतर पारदर्शिता लाना और ई-गवर्नेंस को मजबूत करना है। प्रत्येक पीआरआई को आवंटित अद्वितीय कोड के माध्यम से ईग्रामस्वराज पोर्टल और स्थानीय सरकार निर्देशिका के बीच एक सहज एकीकरण है जो अन्य पीईएस के साथ अंतःक्रियाशीलता की अनुमति देता है।

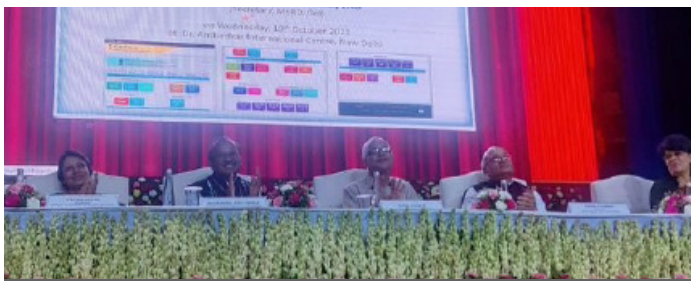

लोक योजना अभियान पर दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संशोधित ईग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ किया

हाल ही में, ई ग्राम स्वराज पी एफ एम एस इंटरफेस (eGSPI) के माध्यम से संसाधित कुल लेनदेन मूल्य रुपये को पार कर गया। 1 लाख करोड़, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसने जमीनी स्तर पर डिजिटल क्रांति को सक्षम बनाया है।

– सूचना विज्ञान समाचार डेस्क, एनआईसी–मुख्यालय

माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश ने ईआईएलपी पोर्टल का शुभारंभ किया

अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने ई-इनर लाइन परमिट (ईआईएलपी) जारी करने के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान श्री वांगकी लोवांग, माननीय आईटी मंत्री और श्री नकाप नालो, माननीय अरुणाचल राज्य के पर्यटन मंत्री की उपस्थिति में ईआईएलपी पोर्टल लॉन्च किया है।

पोर्टल राज्य में तेज, अधिक सुविधाजनक और सुगम प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगा। यह प्रतीक्षा अवधि को कम करके और आवेदन अनुमोदन प्रक्रिया को निर्धारित करके पर्यटकों के लिए इनर लाइन परमिट (आईएलपी) प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा।

पर्यटक एक आधिकारिक आईडी कार्ड जैसे आधार, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट जमा करके क्यूआर कोड आधारित आईएलपी बना सकता है। इस क्यूआर कोड आधारित आईएलपी को विशेष रूप से डिजाइन किए गए मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन का उपयोग करके चेक गेट्स पर पुलिस कर्मियों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है, इस प्रकार पर्यटकों को तेज आवागमन की सुविधा मिलती है।

– देवाशीष नाथ, अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, श्री पेमा खांडू ने राज्य में प्रतिबंधित और संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए ईआईएलपी पोर्टल लॉन्च किया

ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री ने एसएएसीएआर पोर्टल का शुभारंभ किया

ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री, श्री नवीन पटनायक ने राज्य भर में पंजीकृत एससी-एसटी अत्याचार मामलों के प्रसंस्करण के लिए एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करने के लिए SAACAR (सिंगल विंडो एप्लीकेशन अत्याचार मुआवजा सहायता और राहत) पोर्टल का उद्घाटन किया। माननीय मुख्यमंत्री ने पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि पोर्टल 21 दिनों की अवधि के भीतर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार के मामलों में पीड़ितों को तेजी से जांच और मुआवजे के भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल दक्षता में वृद्धि करेगा और पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान और जांच की मौजूदा मैन्युअल प्रणाली के कारण होने वाली देरी से बचाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह नया पोर्टल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित अत्याचार के पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत लाएगा।

– हरा प्रसाद दास, ओडिशा

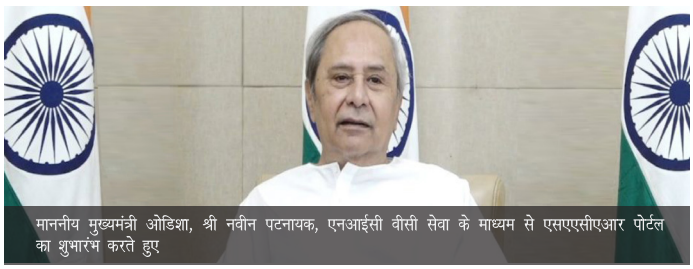

माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा, श्री नवीन पटनायक, एनआईसी वीसी सेवा के माध्यम से एसएएसीएआर पोर्टल का शुभारंभ करते हुए

तमिलनाडु पुलिस ने टीएनपीईएसआर प्रणाली शुरू की

तमिलनाडु पुलिस सिस्टम को अपडेट करने के प्रयास में, तमिलनाडु पुलिस विभाग ने पूरे राज्य में टीएनपीईएसआर (तमिलनाडु पुलिस इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस रजिस्टर) सिस्टम को आधिकारिक रूप से चालू करना शुरू कर दिया है।

टीएनपीईएसआर जनशक्ति, सेवा विवरण, प्रतिनियुक्ति विवरण और किसी भी अन्य संबंधित जानकारी का सटीक दृष्टिकोण प्रदान करने जा रहा है। इसमें कई डैशबोर्ड हैं जो बेहतर निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करते हैं और ऊपरी प्रबंधन को संगठन के भीतर काम करने वाले प्रमुख संसाधनों की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने, विकसित करने, प्रबंधित करने और प्रेरित करने की क्षमता प्रदान करते हैं।

सिस्टम का शुभारंभ डॉ. सी. सिलेंद्र बाबू, आई.पी.एस. द्वारा किया गया, जो तमिलनाडु राज्य के पुलिस महानिदेशक हैं। उन्होंने एनआईसी तमिलनाडु द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

– बीना सी., तमिलनाडु

डॉ. सी. सिलेंद्र बाबू, डीजीपी, तमिलनाडु पुलिस टीएनपीईएसआर प्रणाली का उद्घाटन करते हुए

माननीय उद्योग मंत्री केरल ने KOMPAS पोर्टल लॉन्च किया

माननीय उद्योग मंत्री, केरल, श्री पी. राजीव ने राज्य में खानों और खनिजों से संबंधित नागरिक केंद्रित सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए केरल ऑनलाइन खनन परमिट प्रदान करने वाली सेवाएं (KOMPAS) पोर्टल लॉन्च किया।

आयोजन के दौरान, माननीय मंत्री ने कहा कि केरल में भी कम पर्यावरणीय प्रभाव वाली खनन गतिविधियों को लागू करने के लिए बेहतर प्रणाली लाने की आवश्यकता है और सुझाव दिया कि KOMPAS इन गतिविधियों में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि फाइलों को लंबित न रहने दें और आवेदन प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। भविष्य में ऐसी व्यवस्था होगी जहां गैर-लक्जरी भवनों के निर्माण के लिए संबंधित स्थानीय निकाय स्वयं मिट्टी बदलने की अनुमति दे सकते हैं।

KOMPAS पोर्टल में चार मॉड्यूल शामिल हैंरू 1. उत्खनन परमिट - लघु अवधि परमिट (1 हेक्टेयर क्षेत्र तक और एक वर्ष की अवधि तक); 2. उत्खनन पट्टा - दीर्घकालिक परमिट (12 वर्ष तक); 3. सी. आर.पी.एस परमिट - अल्पावधि परमिट (0.5 हेक्टेयर क्षेत्र तक और एक वर्ष की अवधि तक) और 4. KSWIFT-KOMPAS एकीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से सामान्य मिट्टी के उत्खनन परमिट के लिए आवेदन। पोर्टल को https://www.portal.dmg.kerala.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

– सूसी एम., केरल

पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री, श्री भगवंत मान ने राज्य में खेंगी तकसीम को कारगर बनाने के लिए समर्पित सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया

देशभर में ई-शासन गतिविधियों के बारे में नवीनतम व अद्यतन समाचारों व सूचना के लिए News पर जायें https://informatics.nic.in/news